RAJYA SABHA

Friday, the 27th March, 1992/7 Chaitra, 1914 (Saka)

The House met at eleven of the Clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Job-oriented Education Policy

*401. SHRI ISH DUTT YADAV:†
SHRI SANTOSH BAGRODIA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOUPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to draft a Job-Oriented Education Policy;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what steps Government propose to take to upgrade the quality of education?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) There is already considerable thrust in the National Policy on Education (NPE), 1986, on vocational education with the objective of enhancing individual employability, and reducing the mismatch between demand and supply of skilled manpower (paras 5.16 to 5.23 of the Policy). The need to have a large number of teachers and professionals in vocational education has been recognised (para 6.9). Technical and management education have been dealt with at length in paras 6.1 to 6.11 in the NPE, 1986. There is stress also on work experience organised as an integral part of the learning process (para 8.14 of the Policy). All aspects of a possible job-oriented education policy are, thus, already enshrined in the NPE, 1986.

(c) Several programmes have been lauched for improvement of quality of education. In 1987-88 the scheme of Operation Blackboard was initiated to improve the facilities a primary schools. A number of measures have been taken also to improve the content and process of education. These measures include renewal of curricular improvement of the quality of text-books, in-service training of teachers to improve their professional competence and utilisation of educational technology to bring about improvement in the quality of education.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ish Dutt Yadav.

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, माननीय संसाधन विकास मंत्री जी का जो उत्तर है, इससे यह परिलक्षित होता है कि इस प्रकार की कोई नीति नहीं है और न तो सरकार का कोई इरादा है कि शिक्षा को रोजगार-परख बनाया जाये और जो बेकारी देश के अन्दर बढ़ रही है, उस बेकारी की समस्या को हल करने के लिये शिक्षा को रोजगार परख बनाने की सरकार को कोई नीति नहीं मालूम पड़ती। मान्यवर, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और एक राममूर्ति कमेटी भी शिक्षा में सुधार के लिये बनाई गई थी, लेकिन सरकार ने राममूर्ति कमेटी की संस्तुतियों पर तो विचार ही नहीं किया।

श्री सभापति : : अब आप प्रश्न कर लीजिये। देखिए, सभी लोग सवाल करना चाहते हैं।

प्रश्न काल बहुत महत्व का है। लम्बा आप करेंगे तो फिर.....

श्री ईश दत्त यादव : मैं लम्बा नहीं करूंगा, मान्यवर।

श्री सभापति : दया कीजिये, दूसरे मैम्बरों पर।

श्री ईश दत्त यादव : मैं संक्षेप में ही पूछूंगा।

श्री सभापति प्रश्न पूछ लीजिये, बस।

श्री ईश दत्त यादव : जो 1986 की सरकार की शिक्षा नीति है, मान्यवर,

इस पर भी सरकार ने कोई अमल नहीं किया और माननीय मंत्री जी ने जो मेरे मूल प्रश्न का उत्तर दिया है, उसमें कुछ पैराग्राफ इन्होंने गिना दिये हैं। और, महोदय, जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति से बेकारी बढ़ रही है और बेकारी के साथ-साथ.....

श्री सभापति : प्रश्न क्या है ? प्रश्न, प्रश्न ।

श्री ईश दत्त यादव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, दो मिनट में प्रश्न पूछ लूंगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, दो मिनट में नहीं। तीन मिनट आप ले चुके हैं।

श्री ईश दत्त यादव : एक मिनट, सर। इससे बेकारी की समस्या बढ़ रही है और देश के अन्दर जो उग्रवाद और अपराध बढ़ रहे हैं, इसके मूल में भी एक कारण है, मान्यवर, कि शिक्षित बेरोजगार लोगों का उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शीघ्र इस प्रकार की कोई रोजगार परक शिक्षा नीति तैयार करके उस पर अमल करेगी ताकि शिक्षा समाप्त होते ही लड़के को जीविकोपार्जन के लिये व्यवसाय, काम या नौकरी मिल जाये ? क्या सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके इस प्रकार की नीति, नई शिक्षा की नीति का निर्माण करके उसको अमल में लायेगी ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय, सभापति, महोदय, जहां तक नीति का विषय है, मैंने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 1986 की शिक्षा नीति में इस संबंध में पूरी तरह से व्याख्या है, समावेश है। जहां तक राममूर्ति कमेटी की संस्तुतियों का सवाल है, मैं सदन में पहले भी बता चुका हूं कि इस पर विचार करने के लिये सी.ए.बी. की एक कमेटी बनी है श्री जनार्दन रेड्डी के सभापतित्व में। उन्होंने अपनी संस्तुति दी है। अब सी.ए.बी. में हमको ले जाना पड़ेगा और सी.ए.बी. के निर्णय के अनुसार, सुझाव के अनुसार उस पर अमल किया जायेगा।

जहां तक आपका व्यापक प्रश्न है कि रोजगारोन्मुख शिक्षा के बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं या कोई दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, मेरे मत में उचित नहीं है। बहुत सी चीजें तो इस उत्तर में ही बताई गई हैं, जो उस दिशा में प्रयास किया जा रहा था।

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, इस देश में दोहरी शिक्षा नीति है, कान्वेंट स्कूल, किन्डर गार्टन, सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय और दूसरी तरफ टाट पट्टी वाले प्राइमरी स्कूल हैं, दो तरह की शिक्षा है और यही कारण है कि इस देश में के कुछ लोग, जो अच्छे स्कूल कालेजों में पढ़ते हैं, उनको तो काम मिल जाता है और जो टाट पट्टी वाले स्कूल में पढ़ते हैं, जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को कोई काम नहीं मिल पाता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में जो दोहरी-शिक्षा-व्यवस्था है, इसको समाप्त करके पूरे देश के अन्दर एक शिक्षा-व्यवस्था का पाठ्यक्रम रखेंगे, जिसमें गरीब और अमीर, दोनों के बच्चे एक साथ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें और जिससे कोई भेदभाव न रह सके ? क्या सरकार शीघ्र इस तरह का निर्णय लेगी, देश में एक समान शिक्षा-नीति चालू करेगी ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति जी, शिक्षा एक विषय है, जिसमें राज्य सरकारों को बहुत मूलभूत अधिकार हैं। यह प्रयास रहा है कि न्यूनतम आवश्यकतायें तायें, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्राथमिक स्तर पर, सब जगह समान रूप से उपलब्ध कराई जायें। इस दिशा में काफी प्रगति भी हुई है और भी काम आगे हो रहा है। जहां तक अलग-अलग विद्यालयों में जो आपने जिक्र किया—चाहे वह नवोदय विद्यालय हो या केन्द्रीय विद्यालय हो, उनकी स्थापना की अलग-अलग प्रक्रिया है और उसके संबंध में मैं समझता हूं कि सदन को किसी प्रकार की यह शंका नहीं होनी चाहिये कि हम उसके द्वारा कोई दोहरी नीति अपना रहे हैं।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Chairman, Sir, before I ask my supplementary, I seek one clarification. My original question was: 'What are the steps the Government is going to take in regard to improvement of technical education?' This has not been answered. Under the law, if it is to be done, I would request the hon. Minister to reply to this first, so that I can put my supplementary.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I can certainly reply to what is asked, but I cannot give any explanation in regard to a certain part which was not included in this.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I would lige to know why this was not included in the question.

MR. CHAIRMAN: If you had asked about technical education, he would have replied. But here, you had asked a general question. It says: 'What steps Government propose to take to upgrade the quality of education?'

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I am raising this question here because there is something wrong in the Question Secton. I had given notice one question in the last Session, but this was not allowed.

MR. CHAIRMAN: That we will talk in my Chamber.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Should I also talk to you in your Chamber, Sir?

MR. CHAIRMAN: Now, do you want to put your supplementary?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Yes. Sir, there is need for developing a technical education pattern which should help in achieving National Technology Missions, particularly, those related to water resources, waste land development, and upliftment of the rural and weaker sections of the society. This has been well-establishment is taking for developing this kind of pattern.

SHRI ARJUN SINGH: The specific targeted steps will come in the overall approach to the entire subject of technical education and also vocational education. The AICTE, which was set up in 1987, deals with the standardisation of technical education all over the country, so that the standards and pattern are uniform, and he basic requirements that are needed in technical institutions are made available.

Modernisation and upgradation of infrastructure has been undertaken through various schemes, some of which aided by other countries and also by the World Bank. For example, manpower generation in such areas of technical education. Two major projects with the aid of the World Bank have been undertaken for improving the polytechnic system as a whole, including quality, capacity and efficiency. Then, introduction of a scheme for industry-institution interaction, and modernisation of curriculum and training of teachers. What I want to say is, what the hon. Member is mentioning is certainly very important, but we cannot have separate targetted schemes. In the overall context we will have to provide for all these training programmes.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Sir, I do believe that the question was largely related to vocational education and technical education, but that has been shifted afterwards to upgrade the quality of education and I can understand that it is not the fault of the HRD Ministry. Now the question is that you have just given the policy frame that has been mentioned in any book and elsewhere. The real thing is, what is the implementation? At the moment, as I understand, hardly 15 per cent of the budget of the Central education is spent on vocational education.

श्री सभापति : अब हमने कहा कि वह एक्सपर्ट से पूछने में दिक्कत होती है। अब प्रश्न पूछ लो।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: There are 40....

DR. BAPU KALDATE: An ex-Minister is asking the new Education Minister.

MR. CHAIRMAN: There are other Members who will also like to ask questions.

SHRI ARJUN SINGH: My knowledge is very much limited. I will be grateful to the hon. Member if he enlightens me.

MR. CHAIRMAN: Let him enlighten you outside this House.

SHRI M. A. BABY: Those who represent jobless youths should be given an opportunity.

MR. CHAIRMAN: But they have got the job now. They are re-employed.

DR. BAPU KALDATE: He was about to lose the job.

MR. CHAIRMAN: He is re-employed now.

SHRI N. E. BALARAM: Now he is transferring the exercise to that side.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: My question is that vocational education requires a big thrust. That is what mentioned also, but in the education budget of the Central Government there is hardly 15 per cent allocation for vocational education. While the percentage of the unemployed educated is almost 40 of the total unemployed youth of the country, 55 million are above matriculation who are unemployed. Therefore, this require special emphasis.

MR. CHAIRMAN: If you want specific information, you put it in a question formed and finish it. (*Interruptions*). You are just lecturing what he should do. You ask what he is going to do.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: It is a suggestion for action.

MR. CHAIRMAN: Your suggestion is for consideration.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: My point is, what is the estimate to educate vocationally our students who are in millions and who are being made jobless after they come out of schools and colleges? What is the budget actually required and what are you getting? If you say that you require a notice for this, there is no point in asking Part two of my supplementary is the Ramamurti Committee did go specifically into all these points. Now there is another Committee, Janardhan Committee, which is appointed to review the recommendations of the Ramamurti Committee. Then there will be another Committee of the HRD Minister to go into.

MR. CHAIRMAN: Fourteen minutes are gone.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: What is the time-frame for completing this job-oriented policy, its implementation part?

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I must candidly confess that the total allocation for vocational education which the hon. Members and the hon. Member who has posed this question, does, fall short of what should be in the overall national context. But since that is a matter of general resource mobilisation and allocation, my opinion alone cannot be the deciding factor in that. But, whatever resources we have got, we are trying to see that they are spent in such a manner that vocational education not only improves in content but in it relationship to what the students, who come out of it, get in terms of employment And a number of steps have been taken in that regard. I would only cite one, just as an indication. Sir, up to 1991-92, for these 400 schools which have 12,543 approved sections for importing vocational education, the total expenditure was, approximately, Rs. 256 crores. We have also to improve the content of this education. It is decided to establish a Central Institute of Vocational Education which will impart focus to the preparation of instructional materials, text-books, teacher training, orientation, etc.

श्री भंवर लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी शिक्षाविदों और शिक्षा-शास्त्रियों से बहस कराने के बाद यह जो शिक्षा नीति अपनायी गयी, उसके व्यावसायीकरण में कमी होने का कारण क्या यह है कि माननीय वी० पी० सिंह जी की सरकार और चन्द्रशेखर जी की सरकार द्वारा इस नीति के संबंध में फिर से चर्चा की गयी और इसके अमल में नहीं लाने के कारण उसमें व्यावसायीकरण में कमी आयी ? मेरे प्रश्न का भाग "ब" यह है कि क्या आठवीं कक्षा तक ही जो 120 लाख विद्यार्थी पास करते थे और फिर छोड़ देते थे, वह संख्या क्या अब कम हुई है? वैसे अब विद्यार्थियों ने आठवीं कक्षा और दसवीं कक्षा पास कर के नहीं छोडा है, और आगे पढ़ रहे हैं । तो मेरे प्रश्न का भाग "स" यह है कि श्रम मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों मिलकर, बाल व्यवसाय के लिए जो प्रतिबंध हैं, उसके लिए कक्षा में ही उसे इस प्रकार की पांचवीं क्लास तक व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ताकि श्रमिक लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें और उन्हें आगे शिक्षा मिल सके और वह अपने माता-पिता के लिए रोजगार में कुछ हाथ बटा सके । ऐसा कोई आपका कार्यक्रम है ।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, जहां माननीय सदस्य का पहला प्रश्न है यह उद्देश्य कुछ भी रहा हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन यह सत्य है कि प्रोफेसर राममूर्ति समिति जो बनी थी, उसने समूची शिक्षा नीति के मल्यांकन का एक प्रयास किया और स्वाभाविक है कि वह प्रयास जब हो रहा था तब उसके विभिन्न पहलुओं पर उतना जोरदार अमल नहीं हो सकता था, जब तक कि उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती । उनकी रिपोर्ट आ गयी है ।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: It is not a fact, Sir, everything was done to implement vocational education.

श्री अर्जुन सिंह : उनकी रिपोर्ट आ गयी है, उसमें वोकेशनल एजुकेशन को भी उन्होंने काफी महत्व दिया है और जैसाकि मैंने बताया कि जनार्दन कमेटी ने भी उस पर अपनी समीक्षा दे दी है । अगले महीने या मई महीने के अन्दर सी०ए०बी० की मीटिंग कर के उसे उसके सामने रखूंगा और वहां जो फैसला होगा, उस पर अमल करूंगा ।

SHRI ASHIS SEN: Sir, in this connection I may mention that there is an institute called the All-India Ali Yavar Jung Institute for the Hearing Handicapped. That is an institute which gives training to the teachers who go out to the villages to teach the hearing handicapped children how to speak. The problem here is, this is a vocational training institute but then it is not having the proper number of teachers there. That is one of the major points where the Government should try to see that teachers are made available for vocational training for this purpose. That is my question.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, since this question deals with a specific institution...

MR. CHAIRMAN: He says, vocational training for teaching deaf children. That is the question.....(*Interruptions*). It is a smaller term.

SHRI ASHIS SEN: Yes, for them the training institute is there but, for want of a sufficient number of teachers, it is not becoming possible.

MR. CHAIRMAN: That is the training of teachers for this work.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, there are training institutions, but with relation to this particular institute what the difficulty is I would certainly look into and see that the needful is done.

MR. CHAIRMAN: He will try to do the needful.

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय, आजादी के बाद से देश की शिक्षा नीति के बारे में.... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : आपने वायदा किया था कि ..... **(व्यवधान)**

श्री राम दास अग्रवाल : सभापति महोदय, ज्यादा समय में नहीं लेता, आप जानते हैं।

श्री सभापति : 20 मिनट हो चुके हैं।

श्री रामदास अग्रवाल : शिक्षा नीति का निर्धारण हमारे देश की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिस्थिति और संस्कृति के अनुसार नहीं हो पाया है, यह हम जानते हैं अच्छी तरह से और यही कारण है कि आज हमारे देश में 3 करोड़ बेरोजगार हैं।

श्री सभापति : नहीं, आपका प्रश्न है कि शिक्षा नीति जो है वह संस्कृति के अनुरूप हो, बस यह पूछ लीजिये.... **(व्यवधान)**

श्री रामदास अग्रवाल : वोकेशनल शिक्षा पद्धति प्रारम्भ करने के बारे में भी योजनायें बनी हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन होने में इतना विलम्ब होता है।

श्री सभापति : प्रश्न कीजिय।

श्री रामदास अग्रवाल : प्रश्न मेरा यह है कि महोदय क्या ऐसी वोकेशनल शिक्षा पद्धति जो आप प्रारम्भ करेंगे, ऐसे प्रान्त जैसे राजस्थान है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, जिसमें आदिवासी जनजाति क लोग रहत हैं, पिछड़े वग के लोग रहते हैं, उन बच्चों को शिक्षा देते समय, तकनीकी या वोकेशनल सर्विस देते समय क्या उनको कोई छात्रवृत्तियां देंगे या उनके रहने की कोई व्यवस्था करके किसी छात्रावास में रखने की व्यवस्था करेंगे या फिर उनको रूरल एरियाज में ही आप तकनीकी शिक्षा देने का प्रयत्न करेंगे, यह मरा प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय से।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के बाद से राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप और नये परिवेश में प्रकृति, प्रवृत्ति और आवश्यकता, तीनों को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ है। समय-समय पर उसकी समीक्षा हुई है। देश के महान विद्वानों ने उस समीक्षा के माध्यम से शिक्षा को दिशा दी है। यह कहना कि आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कोई विचार ही नहीं हुआ और हम वहीं खड़े हैं, यह शायद उचित नहीं होगा, न्यायपूर्ण नहीं होगा। जहां तक... **(व्यवधान)**।

श्री रामदास अग्रवाल : 3 करोड़ बेकार कैसे हो गये, हिन्दुस्तान के अन्दर... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : यह डिस्कशन नहीं हो रहा है .....**(व्यवधान)**। आप वह बता दीजिये उनका जो प्रश्न है, दूसरा भाग जो है, जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसमें आप क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के लिये कई विशेष उपाय किये गये हैं। होस्टल एकोमोडेशन उनमें से एक है, छात्रवृत्ति उनमें से एक है। वह सभी जगह लागू होता है। टैक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी लागू होता है। यदि कोई विशेष आवश्यकता और कहीं होगी तो ऐसे समाज के कमजोर वर्ग के लिये शासन हर तरह के प्रयत्न करने के लिये तत्पर है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 402.

श्री रामदास अग्रवाल : मेरा एक पैसिफिक क्वश्चिन था कि इस योजना के अन्तर्गत क्या व्यवस्था की गई है ..... **(व्यवधान)**